दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

सुरक्षित: 19 जनवरी, 2023
उदघोषित: 25 जनवरी, 2024

मू.वि.या. (वाणि.) 456/2022

मेसर्स के.एस. जैन बिल्डर्स ..... याचिकाकर्ता

द्वारा: सुश्री मीनाक्षी ज्योति, श्री धरवीर सिंह और श्री विकास सिंह, अधिवक्तागण के साथ श्री संजीप जैन, अति.प्रति.।

बनाम

भारतीय रेल कल्याण संगठन ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री सुलेमान मोहम्मद खान, सुश्री तैबा खान, श्री भानू मल्होत्रा और श्री गोपेश्वर सिंह चंदेल, अधिवक्तागण।

कोरमः
माननीय न्यायाधीश श्री संजीव नरूला

निर्णय

न्या. संजीव नरूला

1. याचिकाकर्ता (माध्यस्थम में दावेदार), माध्यस्थम में सफल पक्षकार होने के बावजूद, एकल माध्यस्थम द्वारा दिए गए 7 जुलाई, 2022 के माध्यस्थम पंचाट

से असंतुष्ट है। उनकी चुनौती दो विशिष्ट दावों यानी दावा सं. 4 और 5 पर निष्कर्षों की ओर निर्देशित है, जिनकी केवल आंशिक रूप से अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये निष्कर्ष 'पेटेंट अवैधता' को प्रदर्शित करते हैं और यह कि आक्षेपित पंचाट 'नैतिकता और न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं' और 'भारतीय विधि की मौलिक नीति' के साथ संघर्ष में है। इसके विपरीत, प्रत्यर्थी का तर्क है कि पंचाट त्रुटिहीन है, और याचिकाकर्ता की चुनौती का आधार माध्यस्थम और सुलह अधिनियम, 1996 ("अधिनियम") की धारा 34 में उल्लिखित किसी भी अनुज्ञेय मानदंड के तहत नहीं आता है। यह इस न्यायालय के विचार के लिए मुख्य विवाद को समाहित करता है।

2. दोनों पक्षकारों के बीच विवाद 12 अप्रैल, 2016 के अनुबंध पंचाट ("एल.ओ.ए") से उत्पन्न हुआ। 33,52,66,929/- रुपए मूल्य के इस अनुबंध में उत्तर प्रदेश के गाँव मिरानपुर-पिनवत, परगना-बिजनौर, तहसील और जिला लखनऊ में एक आवासीय परिसर का निर्माण शामिल था और इसे एल.ओ.ए. जारी होने के तीस महीने के भीतर पूरा किया जाना था। याचिकाकर्ता का दावा है कि वे काम शुरू करने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रत्यर्थी ने निर्माण योजनाओं की मंजूरी में देरी का हवाला देते हुए आरम्भ में बाधा डाली। इसके अलावा, उनका दावा है कि परियोजना की लागत को और कम कर दिया गया था क्योंकि लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण ("एल.आई.डी.ए".) ने 144 आवासीय इकाइयों की तुलना में

केवल 126 आवासीय इकाइयों को मंजूरी दी थी, जिसके लिए शुरू में प्रत्यर्थी द्वारा निविदा जारी की गई थी। आवश्यक अनुमोदन और पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही काम शुरू हुआ, जिसके कारण एल.आई.डी.ए. द्वारा योजनाओं की मंजूरी के बाद 15 फरवरी 2018 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते के अनुसार, काम पूरा करने के लिए 30 महीने की अवधि बैंक गारंटी जमा करने की तिथि से यानी 02 फरवरी, 2018 से शुरू होगी।

3. याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि प्रस्ताव (एल.ओ.ए.) की स्वीकृति की तिथि से दो साल और सात महीने बीतने और 15 फरवरी 2018 के समझौते के बाद नौ महीने बीतने के बावजूद काम शुरू नहीं किया जा सका क्योंकि प्रत्यर्थी ने उन्हें केवल 13 नवंबर 2018 को पर्यावरण मंजूरी की प्राप्ति के बारे में सूचित किया था। इसके बाद, हालांकि उन्होंने अग्रिम काम शुरू किया, लेकिन प्रत्यर्थी द्वारा आवश्यक मात्रा में इस्पात की आपूर्ति करने में विफलता के कारण इसे बार-बार व्यवधानों का सामना करना पड़ा। उनका तर्क है कि अनुबंध की विशेष शर्तों ("एस.सी.सी".) के खंड 5.3 के अनुसार, प्रत्यर्थी बिना किसी अतिरिक्त लागत के काम के निष्पादन के लिए प्रबलन इस्पात की आपूर्ति करने के लिए बाध्य था। आवश्यक निर्माण इस्पात की आपूर्ति के लिए याचिकाकर्ता के बार-बार किए गए अनुरोधों पर ध्यान नहीं दिया गया। सितंबर 2020 में, याचिकाकर्ता ने प्रत्यर्थी से सामग्री की आपूर्ति के मुद्दे को संबोधित करने या माध्यस्थम का सामना करने

का आग्रह किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बजाय, 28 अक्टूबर 2020 को, प्रतिवादी ने कोविड-19 महामारी और अचल संपत्ति क्षेत्र में मंदी का हवाला देते हुए परियोजना को एकतरफा रूप से स्थगित कर दिया। इसके बाद 02 फरवरी 2021 को वैश्विक महामारी के कारण आकस्मिक घटना के आधार पर अनुबंध समाप्त कर दिया गया।

4. याचिकाकर्ता ने बाद में माध्यस्थता आरम्भ की, पर्याप्त नुकसान के लिए दावे दायर किए, जिसमें संसाधन लग्नता और लाभ का नुकसान शामिल था। इन दावों का परिणाम इस प्रकार था:

क्र.सं.	*दावा संख्या*	*दावा राशि रु.*	*पुरस्कार राशि रु.*
1	*दावा सं. 1- घोषणात्मक प्रकृति का*	*शून्य*	*शून्य*
2	*किए गए कार्य के लिए बिल सं. 6 के प्रति दावा सं. 2*	*7,64,872,00 और 18/03/2020 से भुगतान की तिथि तक ब्याज दर 15%*	*बिल सं. 6 (अंतिम बिल) किए गए कार्य के लिए पक्षकारों के बीय तय किया जाता है और माध्यस्थम कार्यवाही के दौरान दावेदार को भुगतान किया जाता है। अत: अब इस संबंध में कोई विवाद/दावा नहीं है।*
3	*दावा सं. 3 वृद्धि की ओर*	*1430000.00 और 18/03/2020 से भुगतान की तिथि तक 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज।*	*पक्षकारों के बीच वृद्धि बिल का निपटारा किया जाता है और माध्यस्थम कार्यवाही के दौरान दावेदार को भुगतान किया जाता है। अंत:, अब इस संबंध में कोई विवाद/दावा नहीं है।*
4	*दावा सं. 4 साइट पर*	*73,00,295,00 लागू*	*45,29,089.00*

	वास्तविक खर्चों के प्रति	*जीएसटी और 15% प्रति वर्ष ब्याज दरके साथ। दावा दाखिल करने की तिथि से वास्तविक भुगतान तक।*	
5	*पूर्ववत कार्य पर लाभ की हानि के लिए दावा सं. 5 क्योंकि प्रत्यर्थी द्वारा बीच में कार्य बंद कर दिया गया था।*	*3,85,57,064.00*	*86,01,230.00*
6	*दावा संख्या 6 माध्यस्थम लागत की ओर।*	*22,08,607.00 दिनांक 02/03/2022 के अंतिम निर्णायक विवरण में प्रस्तुत वास्तविक आंकड़ो के अनुसार ।*	*11,04,303.00*
कुल दावे 4, 5 और 6		*4,82,73,966/- +ब्याज*	*1,42,34,622.00*

5. प्रत्यर्थी के प्रतिदावों को खारिज कर दिया गया और उनके पक्ष में कोई पंचाट नहीं दिया गया। संक्षेप में, दावेदार पंचाट के प्रकाशन की तिथि से भुगतान की तिथि तक 8 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ 1,42,34,622/- रुपए का पंचाट प्राप्त करने में सफल रहा।

6. वर्तमान याचिका में चुनौती, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा लिखित प्रस्तुति में स्पष्ट किया गया है, दावा सं. 5 के संबंध में दावे के अधिनिर्णय तक सीमित है, जो निम्नानुसार हैं:

> "*10.4.5 माध्यस्थम अधिकरण ने पहले ही अनुबंध के उल्लंघन पर पैरा 9.4 से 9.4.3 में विस्तृत विचार-विमर्श किया है और माना है कि अनुबंध का उल्लंघन प्रत्यर्थी की ओर से हुआ है। भारतीय अनुबंध अधिनियम-1872 की धारा 73 के अनुसार, अनुबंध का उल्लंघन करने वाला पक्ष उल्लंघन के कारण हुए नुकसान के लिए दूसरे पक्ष को क्षतिपूर्ति करने के लिए उत्तरदायी है। उद्धरण निम्नानुसार है-*
>
> *XXX XXX XXX*
>
> *अब सवाल यह आता है कि क्या प्रत्यर्थी की ओर से उल्लंघन के कारण लाभ की हानि इस धारा 73 के तहत क्षति के परिसर में आती है। माध्यस्थम अधिकरण की राय में, काम पूरा होने पर लाभ की उम्मीद करना दोनों पक्षकारों को ज्ञात अनुबंध का एक स्वाभाविक परिणाम है, प्रत्यर्थी के पत्र दिनांक 28/10/2020 के अनुसार ठेकेदार की कोई गलती नहीं होने के कारण अनुबंध को बंद करना, वह भी ठेकेदार को काम पूरा होने की अवधि या उससे भी अधिक समय तक काम पर रखने के बाद, निश्चित रूप से ठेकेदार को लाभ का नुकसान हुआ है।*
>
> *XXX XXX XXX*
>
> *10.4.7 उसमें चर्चा के अनुसार, माध्यस्थम अधिकरण ने उपरोक्त मुद्दा सं. 1 और 2 पर अपना निष्कर्ष दिया है और माना है कि परियोजना को मंजूरी प्राप्त करने में प्रत्यर्थी की चूक और प्रबलन इस्पात की आपूर्ति नहीं करने के कारण बंद कर दिया गया था और काम पूरा करने में देरी प्रत्यर्थी की चूक के कारण हुई थी।*

10.4.8 प्रत्यर्थी की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के कारण नुकसान का दावा करने के लिए, दावेदार ने शेष अनिष्पादित कार्य पर 15% की दर से लाभ की हानि का दावा किया। लेकिन भारतीय रेलवे कल्याण संगठन के अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 4.3 (iii) के संदर्भ में, यह देखा गया है कि लागत अनुमान में 10 प्रतिशत तक अधिभार और लाभ के लिए एक अनुबंध है।

10.4.9 इसे ध्यान में रखते हुए माध्यस्थम अधिकरण दावेदार को लाभ के नुकसान के लिए मुआवजा देना उचित समझता है जो दावेदार द्वारा अनुबंधित कार्य के पूरा होने पर अर्जित किया गया होगा। भारतीय रेलवे कल्याण संगठन के अनुबंध की सामान्य शर्तों अनुबंध की सामान्य शर्तों के पैरा 4.3 (iii) के अनुसार 10 प्रतिशत का प्रावधान अधिभार और लाभ के लिए है, दोनों भागों को समान मानने का मतलब है कि 5 प्रतिशत लाभ के लिए है। इसके अलावा कार्य अनुबंध में कार्य का दायरा लगभग अनुमानित है और इसलिए उस खाते पर किसी भी दावे के बिना उचित परिवर्तन हो सकता है। मौजूदा मामले में अनुबंध समझौते के खंड 2.4.1 में अनुबंध मूल्य के 25% तक कार्य के दायरे में कमी के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है। इसलिए, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि प्रत्यर्थी कार्य के दायरे को 25 प्रतिशत तक कम कर सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, कार्य का कम दायरा रु. 27,12,80,107.00/- X 0.75=रु. 20,34,60,080.25/- की राशि के लिए हो सकता था। निष्पादित कार्य का मूल्य निश्चित रूप से रु. 1,42,33,015.00/- था। तदनुसार, कार्य का शेष मूल्य रु. 20,34,60,080.25/- - 1,42,33,015.00/- = रु. 18,92,27,065.25/- पर आता है।

***निष्कर्ष** : तदनुसार, कार्य की लागत में अंतर्निहित लाभ भाग की राशि का अनुमान 86,01,230.00/- रुपए, यानी, (18,92,27,065.25/1.10 = 17,20,246,04.772) का 5 प्रतिशत लगाया जा सकता है और इसे*

प्रत्यर्थी द्वारा दावेदार को देय माना जाता है। तदनुसार मुद्दा सं. 5 और दावा सं. 5 का निर्णय लिया जाता है।"

<u>दलीलें</u>

7. याचिकाकर्ता की अधिवक्ता सुश्री मीनाक्षी ज्योति का तर्क इस प्रकार है:

7.1 आक्षेपित पंचाट अधिनियम की धारा 34, विशेष रूप से धारा 34(2)(ख)(ii) और धारा 34 (2क) का उल्लंघन करता है, क्योंकि यह भारतीय विधि की मौलिक नीति का उल्लंघन करता है, नैतिकता या न्याय की सबसे बुनियादी धारणाओं के साथ संघर्ष करता है और पेटेंट अवैधता से ग्रस्त है। इस प्रकार यह इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की गारंटी देता है।

7.2 याचिकाकर्ता ने अपने दावों का समर्थन करने के लिए व्यापक साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिनमें से सभी की आक्षेपित पंचाट में सावधानीपूर्वक जांच की गई है। बहरहाल, यह हैरान करने वाली बात है कि दावा नं. 5 को केवल आंशिक रूप से बरकरार रखा गया था। जबकि माध्यस्थम अधिकरण ने साक्ष्यों की व्यापक रूप से समीक्षा की है, उन्होंने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की अनदेखी की है। इसके अलावा, अधिकरण ने अनुबंध की शर्तों को लागू किया जो न केवल अप्रासंगिक थे बल्कि प्रत्यर्थी द्वारा अनुरोध या तर्क भी नहीं थे। इस दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप स्पष्ट अवैधता सामने आई है, जो अभिलेख से स्पष्ट है।

7.3 माध्यस्थम अधिकरण ने निर्णय के परिचालन भाग में अपने स्वयं के निष्कर्षों का विरोध किया है और अनुबंध की शर्तों को लागू किया है जो पक्षकारों के बीच तथ्यों और विवादों पर लागू नहीं थे।

7.4 माध्यस्थम अधिकरण ने भारतीय रेलवे कल्याण संगठन (आई.आर.डब्ल्यू.ओ.) की अनुबंध की सामान्य शर्तों (जी.सी.सी.) के खंड 4.3 (3) पर भरोसा करके काम के मूल्य के 10 प्रतिशत की दर से 'लाभ की हानि' शीर्ष के तहत दावे को कम करने में अवैधता की है, जो अतिरिक्त, परिवर्तित या प्रतिस्थापित काम के संबंध में था। यह खंड दावा सं. 5 को नियंत्रित नहीं करता था। याचिकाकर्ता ने यह स्थापित करने के लिए प्रासंगिक साक्ष्य प्रस्तुत किए थे कि ठेकेदारों के लाभ के पक्ष में 15 प्रतिशत की वापसी की दर को कार्य के दायरे में विधिवत रूप से शामिल किया गया था। प्रत्यर्थी ने ठेकेदारों के लाभ के रूप में 15 प्रतिशत की दर से इनकार नहीं किया, लेकिन प्रस्तुत किया कि 15 प्रतिशत में 7.5 प्रतिशत की दर से अधिभार शामिल है और ठेकेदारों का लाभ केवल 7.5 प्रतिशत है। प्रत्यर्थी ने सी.पी.डब्ल्यू.डी. परिपत्र सं./डी.जी./एम.ए.एन/150 और डी.जी./एम.ए.एन./184 7.5 प्रतिशत ठेकेदारों के लाभ और 7.5 प्रतिशत अधिभार के बारे में दायर किया था। यह प्रत्यर्थी का स्वीकृत मामला था कि उक्त परियोजना के लिए ठेकेदारों का लाभ 7.5 प्रतिशत था। इस प्रकार माध्यस्थम अधिकरण भारतीय रेलवे कल्याण संगठन के अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड

4.3 (iii) पर भरोसा नहीं कर सकता था। इस प्रकार, पैराग्राफ 10.4.8 में निष्कर्ष पूरी तरह से गलत है और यह प्रत्यर्थी का मामला भी नहीं था। इसके अलावा, आक्षेपित पंचाट के पैराग्राफ 10.4.9 पर अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 2.4.1 का अनुप्रयोग, कार्य के दायरे को अनुबंध मूल्य के 25% तक कम करना भी अभिलेख में स्पष्ट रूप से गंभीर त्रुटि है और यह दिमाग के गैर-अनुप्रयोग को दर्शाता है। था,माध्यस्थम अधिकरण ने इस तथ्य यहां तक कि यह मानते हुए कि अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 2.4.1 को लागू किया जा सकता था, हालांकि दलील या तर्क नहीं दिया गया को नजरअंदाज करके गंभीर त्रुटि की कि प्रत्यर्थी द्वारा अनुबंध मूल्य में पहले ही 23 प्रतिशत की कमी कर दी गई थी और इसलिए, परियोजना के कुल मूल्य में 25 प्रतिशत की कमी एक स्पष्ट त्रुटि थी। इस प्रकार, प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकार किए गए और दरों के सी.पी.डब्ल्यू.डी. विश्लेषण के अनुसार, याचिकाकर्ता 7.5% की दर से कार्य मूल्य की शेष राशि पर लाभ के नुकसान का हकदार था।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी के अधिवक्ता ने यह तर्क देते हुए आक्षेपित पंचाट का दृढ़ता से बचाव किया है कि अधिनियम की धारा 34 के तहत इस न्यायालय के हस्तक्षेप के संकीर्ण दायरे को देखते हुए याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किए गए किसी भी आधार पर विचार नहीं किया जा सकता है। किसी भी आधार को स्वीकार

करना साक्ष्य की पुनः प्रशंसा के बराबर होगा जो अधिनियम की धारा 34 के तहत अनुज्ञेय नहीं है।

<u>विश्लेषण और निष्कर्ष</u>

9. सबसे पहले याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई प्रार्थना को उपवर्णित करना महत्वपूर्ण है:

> *"क) दावा सं. 4 और दावा सं. 5 के तहत देय शेष राशि को स्वीकार करने के लिए दिनांकित 07.07.2022 के आंशिक माध्यस्थम पंचाट को अपास्त कर दें।"*

10. 19 जनवरी 2024 को, जब मामले को स्पष्टीकरण के लिए फिर से सूचीबद्ध किया गया था, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि जबकि याचिका में मूल रूप से दावा सं. 4 के संबंध में माध्यस्थम अधिकरण के निष्कर्षों का विरोध किया गया था, वे अब इस चुनौती का पालन नहीं कर रहे हैं। दावा सं.5 के संबंध में, अधिवक्ता ने निम्नानुसार स्पष्टीकरण दिया:

> *"3. ...*
> *याचिकाकर्ता के अधिवक्ता स्पष्ट करता है कि मध्यस्थ द्वारा दिए गए दावे का हिस्सा प्रत्यर्थी द्वारा पहले ही भुगतान कर दिया गया है, और याचिकाकर्ता द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया है। इसलिए, याचिकाकर्ता की चुनौती केवल दावे के उस हिस्से तक सीमित है जिसे आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया था।"*

11. इसके बाद, एक आवेदन [अं.आ. सं. 1614/2024] के द्वारा, अधिवक्ता ने उसके पहले के निवेदन को वापस लेने की मांग की। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायालय के प्रश्न पर उनका पूर्व-उल्लिखित उत्तर गलत था और याचिकाकर्ता ने दावा सं. 5 से संबंधित पंचाट की संपूर्णता को चुनौती दी है।

12. दावा सं. 5 से जुड़े मुद्दों का व्यापक मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए, न्यायालय अब अधिवक्ता के अलग-अलग रुख के आलोक में प्रस्तुत दो परिदृश्यों को संबोधित करने के लिए तैयार है। इसमें दावा सं. 5 की चुनौती की जांच, विशेष रूप से दावे के अस्वीकृत हिस्से के संबंध में, और उस स्थिति का आकलन भी शामिल है जिसमें चुनौती संपूर्ण निष्कर्षों को शामिल करती है।

13. दावा सं. 5 के लिए पंचाट को उस हद तक अपास्त करने की प्रार्थना, जिस हद तक इसे अस्वीकार कर दिया गया है, मान्य नहीं है। यह निर्विवाद तथ्य है कि 18 अगस्त, 2022 को याचिकाकर्ता को दावा सं. 5 के तहत दी गई राशि पहले ही मिल चुकी है। यह स्वीकृति उन्हें ***स्पोर्टी सॉल्यूशनज़ प्राइवेट लिमिटेड बनाम बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और अन्य*** मामले में आयोजित पुरस्कार को चुनौती देने से रोक देगी,

> *"एक व्यक्ति जो पंचाट के तहत देय लागत या पंचाट के तहत किसी अन्य लाभ को स्वीकार करता है, योग्यता के आधार पर दावा खारिज कर देता है, वह उसके लिए हानिकारक पुरस्कार के हिस्से को अस्वीकार नहीं कर सकता*

*है क्योंकि आदेश पूरी तरह से प्रभावी होना है। **श्री तुषार कांति राय बनाम** आठवां औद्योगिक याधिकरण, कोलकाता और अन्य देखें 2013 (2) सी.एल.जे. (कैल) 620; कावेरी कॉफी ट्रेडर्स बनाम ऑनर रिसोर्सेज (2011) 10 एस.सी.सी. 420 और राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास और निवेश निगम बनाम डायमंड एंड जेम डेवलपमेंट कार्पोरेशन। लिमिटेड, (2013) 5 एस.सी.सी. 470 देखें।"*

14. इसके अलावा, केवल उक्त दावे के अस्वीकृत हिस्से के लिए याचिकाकर्ता की चुनौती पर निम्नलिखित अतिरिक्त कारणों से विचार नहीं किया जा सकता है:

14.1 ***भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण बनाम एम. हकीम और अन्य*** में उच्चतम न्यायालय के निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि न्यायालय अधिनियम की धारा 34 के तहत माध्यस्थम पंचाट को संशोधित नहीं कर सकता है। हालाँकि, यह निर्णय न्यायालय को किसी पंचाट को आंशिक रूप से अपास्त करने से नहीं रोकता है, लेकिन किसी पंचाट में बदलाव या उपांतरण करने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार, आंशिक बातिलीकरण के लिए एक याचिका पर विचार करते समय, न्यायालय को माध्यस्थम पंचाट की पृथक्करणीयता के सिद्धांत को नियोजित करना चाहिए, जो अधिनियम की धारा 34 (2) (क) (iv) में दिए किए गए सिद्धांत से उत्पन्न होता है। यह सिद्धांत न्यायालय को पंचाट के विशिष्ट और स्वायत्त खंडों को बातिल करने में सक्षम बनाता है, बशर्ते कि ऐसे खंड अलग किए जा सकें और पंचाट के शेष भागों को प्रभावित न करें।

14.2 वर्तमान मामले में, दावा सं.5, लाभ के नुकसान के संबंध में, माध्यस्थ द्वारा दिए गए नुकसानी की मात्रा पर विवाद शामिल है। याचिकाकर्ता पंचाट को इस हद तक अपास्त करना चाहता है कि उनके दावों को कम माना गया है। हालाँकि, न्यायालय इस दृष्टिकोण को असमर्थनीय मानता हैशेष कार्य के मूल्य के 5% के रूप में निर्धारित विशिष्ट क्षति का निर्धारण एक विशेष दर पर क्षति देने के औचित्य के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। नतीजतन, दावा किए गए नुकसानी से इनकार करने से संबंधित निर्णय याचिकाकर्ता के पक्ष में दर का निर्धारण करने में नियोजित तर्क से अविभाज्य हैं।

14.3 इस प्रकार, निष्कर्षों और तर्क की परस्पर प्रकृति विवाद को हल करने में अधिकरण के समग्र दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। माध्यस्थम अधिकरण, अपनी विशेषज्ञता में, इन दावों का मूल्यांकन इस तरह से किया है जहां व्यक्तिगत तत्व केवल संबंधित नहीं हैं बल्कि उनके तर्क के लिए एक-दूसरे पर निर्भर हैं। आंशिक बातिलीकरण के उद्देश्य से इन तत्वों को विच्छेदित करने से न केवल न्यायाधिकरण की निर्णय लेने की प्रक्रिया की अखंडता कमजोर होगी, बल्कि एक अंश में और संभावित रूप से असंगत न्यायनिर्णयन भी होगा। इसलिए, न्यायालय को दावों के अधिकरण के संलागी मूल्यांकन का सम्मान करते हुए सावधानीपूर्वक चलना चाहिए, और ऐसे पंचाट को खंडित करने से बचना चाहिए जहां सविरोध घटक स्पष्ट रूप से अलग नहीं हैं। यह दृष्टिकोण अधिनियम की योजना और

माध्यस्थम पंचाटों की अंतिमता से संबंधित विधिशास्त्र के साथ संरेखित होता है। इसलिए, दावा सं. 5 से संबंधित पंचाट के कुछ हिस्सों को अपास्त करने के लिए स्पष्ट, स्वतंत्र आधारों की अनुपस्थिति में, न्यायालय को अधिकरण के निर्णय को पूरी तरह से बनाए रखना प्रज्ञापूर्ण लगता है।

15. वैकल्पिक रूप से, न्यायालय ने यह भी विचार किया है कि क्या याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 34 के तहत दावा सं. 5 के संपूर्णता पंचाट को अपास्त करने के लिए कोई आधार स्थापित करने में समर्थ रहा है।

16. जैसा कि ऊपर चर्चा की गई है, माध्यस्थम अधिकरण ने कम कार्य मूल्य के आधार पर नुकसानी (ठेकेदारों के लाभ का प्रतिनिधित्व करने वाले) में 5 प्रतिशत का निर्णय सुनाया। याचिकाकर्ता यह तर्क देते हुए इसे चुनौती देता है कि अनुबंध की सामान्य शर्तों का खंड 2.4.1, अनुबंध समझौते का अभिन्न अंग, लागू नहीं किया जाना चाहिए था। उनका यह भी तर्क है कि अनुबंध की सामान्य शर्तों का खंड 4.3(iii) ठेकेदारों के लाभ की गणना के लिए लागू नहीं था। इसके बजाय, उनका सुझाव है कि प्रत्यर्थी को भारत सरकार के केंद्रीय निर्माण विभाग के दरों के विश्लेषण, 2016 ("सी.पी.डब्ल्यू.डी") का पालन करना चाहिए था। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का मानना है कि संदर्भित सी.पी.डब्ल्यू.डी. परिपत्रों के अनुसार पंचाट दर कम से कम 7.5% होना चाहिए ।

17. न्यायालय उपरोक्त आधारों में कोई योग्यता नहीं पाता है। यह एक सुस्थापित विधिक पुरोभाव्य है कि यदि माध्यस्थम अधिकरण का दृष्टिकोण प्रशंसनीय है, तो हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। याचिकाकर्ता का यह तर्क गलत है कि आक्षेपित पंचाट 'भारत की सार्वजनिक नीति' के साथ टकराव में है और 'पेटेंट अवैधता' से ग्रस्त है। याचिकाकर्ता का यह आधार कि माध्यस्थ ने अनुबंध की शर्तों को लागू किया है जो अनुपयुक्त है और प्रत्यर्थी द्वारा अनुरोध नहीं किया गया है, इसलिए 'भारतीय विधि की मौलिक नीति' और 'न्यायाधीश या नैतिकता की सबसे बुनियादी धारणाओं' का उल्लंघन है, असमर्थनीय है क्योंकि माध्यस्थ को 'लाभ की हानि' की दर निर्धारित करते समय अनुबंध को समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है। इसलिए, याचिकाकर्ता द्वारा आग्रह किए गए आधार 'भारत की सार्वजनिक नीति' की परिभाषा का अनुप्रयोग नहीं करते हैं, जिसकी उच्चतम न्यायालय द्वारा व्यापक रूप से व्याख्या की गई है और साथ ही अधिनियम की धारा 34(2)(ख)(ii) के स्पष्टीकरण I में संहिताबद्ध किया गया है। लाभ के नुकसान के मुद्दे का आकलन करने में, अधिकरण द्वारा नुकसानी के लिए 5 प्रतिशत दर का निर्धारण, जिसे विवादास्पद भी माना जाता है, पेटेंट अवैधता के स्तर तक नहीं बढ़ता है। ऐसे मामलों में खोए हुए लाभ की गणना स्वाभाविक रूप से अटकलबाजी है और अक्सर काल्पनिक परिदृश्यों पर आधारित होती है। इसलिए, नुकसानी के रूप में 5 प्रतिशत की दर देने का माध्यस्थम अधिकरण का

निर्णय उसकी शक्ति के दायरे में आता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता का दावा किसी भी प्रदर्शित वास्तविक नुकसान पर आधारित नहीं था, बल्कि संभावित लाभों की धारणाओं पर आधारित था जो प्राप्त किए जा सकते थे। वास्तविक नुकसान के ठोस साक्ष्य के बिना इस तरह के अटकलबाजी वाले दावे, अधिकरण के निर्णय को स्पष्ट रूप से अवैध के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पर्याप्त आधार प्रदान नहीं करते हैं।

18. यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि पेटेंट अवैधता का निर्धारण करने की सीमा अधिक है। इसमें विधि के एक गलत अनुप्रयोग से अधिक शामिल है; इसके लिए एक गंभीर त्रुटि की आवश्यकता होती है जो वर्तमान मुद्दे के लिए स्पष्ट और मौलिक हो। इस मामले में, जबकि याचिकाकर्ता अधिकरण के एक विशिष्ट संविदात्मक प्रावधान के आवेदन या केवल 5 प्रतिशत नुकसानी देने के उसके निर्णय से असहमत हो सकता है, ये कार्य आवश्यक रूप से न्याय की घोर विफलता या विधि के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं हैं। अधिकरण का पंचाट, लाभ के काल्पनिक नुकसान के अपने मूल्यांकन के आधार पर, अपने व्याख्यात्मक और निर्णय लेने वाले प्राधिकरण की अनुज्ञेय सीमा के भीतर रहता है।

19. इसके अलावा, 5 प्रतिशत की दर से नुकसान का आकलन करने का माध्यस्थम अधिकरण का निर्णय तथ्य के निष्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, जो माध्यस्थम के दौरान प्रस्तुत सामग्री पर आधारित है। प्रत्यर्थी द्वारा परिपत्रों का

केवल संदर्भ याचिकाकर्ता को 7.5 प्रतिशत की दर से लाभ के नुकसान का अधिकार नहीं देता है। उल्लेखनीय है कि विचाराधीन परियोजना को समाप्त कर दिया गया है। इन परिस्थितियों में, अधिकरण ने कम किए गए कार्य मूल्य के 5 प्रतिशत पर नुकसानी देना उचित समझा। इस तरह का निर्धारण युक्तियुक्त और न्यायपूर्ण दोनों है। इस प्रकार, इस संदर्भ और उपलब्ध तथ्यों और साक्ष्यों पर अधिकरण के सावधानीपूर्वक विचार को देखते हुए, अधिकरण पंचाट में न्यायिक हस्तक्षेप का कोई ठोस आधार प्रतीत नहीं होता है। यह एक संतुलित और तर्कपूर्ण मूल्यांकन को दर्शाता है, जो माध्यस्थम निर्णय लेने की स्वीकार्य सीमाओं के भीतर आता है, और पेटेंट अवैधता या भारत की सार्वजनिक नीति के उल्लंघन की किसी भी विशेषता को प्रदर्शित नहीं करता है, जिसके लिए अधिनियम की धारा 34 में स्थापित सिद्धांतों के तहत आक्षेपित पंचाट को अपास्त करने की आवश्यकता होगी।

20. याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि कुछ दस्तावेजों पर विचार न करना या विषय परियोजना में ठेकेदारों के लाभ के संबंध में प्रत्यर्थी के स्वीकृत मामले की अनदेखी करना, पेटेंट अवैधता के बराबर है। हालाँकि, इसे पंचाट को अपास्त करने के आधार के रूप में भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 34 (2क) के प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि "किसी पंचाट को केवल विधि के गलत अनुप्रयोग या साक्ष्य की पुन: समीक्षा के आधार पर अपास्त

नहीं किया जाएगा।" ***रवींद्र कुमार गुप्ता एंड कंपनी बनाम भारत संघ*** में, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि न्यायालय अधिनियम की खंड 34 के तहत साक्ष्य की पुनःसमीक्षा नहीं कर सकते हैं और माध्यस्थ साक्ष्य की गुणवत्ता और मात्रा का एकमात्र न्यायाधीश है। इस न्यायालय की भूमिका माध्यस्थ अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना नहीं है। न्यायालय भी माध्यस्थ के निष्कर्षों और राय को अपने स्वयं के साथ प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि यह अधिनियम की धारा 34 द्वारा निर्धारित सीमाओं को पार कर जाएगा। जब तक मनमानेपन या तथ्यों की गलत व्याख्या का स्पष्ट संकेत नहीं मिलता है जिससे न्यायहानि होती है, तब तक न्यायालय को अधिकरण के तथ्यात्मक निर्धारणों में हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। इस मामले में, दावा सं. 5 के तहत एक विशिष्ट राशि देने का अधिकरण का निर्णय प्रस्तुत साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर एक सुविचारित मूल्यांकन प्रतीत होता है। इसलिए, इन निष्कर्षों में ऐसी कोई खामियां नहीं हैं जो उन्हें माध्यस्थम अधिनियम की धारा 34 के निर्दिष्ट आधारों के तहत चुनौती देने के लिए तैयार करती हैं।

21. पूर्वगामी कारणों से, वर्तमान याचिका में कोई योग्यता नहीं है। तदनुसार, याचिका खारिज कर दी जाती है।

न्या. संजीव नरूला

25 जनवरी, 2024/*डी.नेगी*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*